दिनांक 16-08-2016 को श्री सुदर्शन भगत, माननीय राज्यमंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (DISHA) की बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी में संधारित है।

कार्यवाही,

सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। उपायुक्त, गुमला के द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए उनसे अपना परिचय देने को कहा गया।

तत्पश्चात उपायुक्त द्वारा दिशा के उद्देश्य के संबंध में सभी सदस्यों को जानकारी देते हुए बताया गया कि जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) जिलों के प्रभावी और समयबद्ध विकास के लिए संसद, राज्य विधान मंडलों और स्थानीय सरकारों (पचायतीराज संस्थाओं/नगरपालिका निकायों) के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के उदेश्य की पूर्ति के लिए गठित एक समिति है। इस समिति का कार्य निर्धारित प्रकियाओं और दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की निगरानी करना तथा कार्यक्रमों को प्रभावपूर्ण बनाने हेतु आपसी तालमेल व संकेन्द्रण करना है। वास्तव में, केन्द्र राज्य और स्थानीय सरकारों को सौंपी गई जिम्मेवारियों की संवैधानिक व्यवस्था के तहत विकास, समन्वय एवं निगरानी को बढ़ावा देने के लिए एक व्यवस्था है।

माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा गैरसरकारी संगठन के रूप में विकास भारती, विशुनपुर एवं अनुसूचित जनजाति के एक प्रतिनिधि के रूप में श्री कमलेश उरॉव, पूर्व विधायक, गुमला विधानसभा क्षेत्र का मनोनयन किया गया।

माननीय अध्यक्ष के द्वारा दिशा की बैठक अप्रैल ,जुलाई, अक्टूॅबर और फरवरी के तीसरे शनिवार को निर्धारित करने का निदेश दिया गया। तद्नुसार अक्टूबर माह की बैठक दिनांक 22.10.2016 को निर्धारित की गई।

उपायुक्त महोदय के द्वारा उपरोक्त मार्गदर्शिकाओं से अवगत कराने के पश्चात दिशा अंतर्गत निर्धारित योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा का सार निम्नवत है :–

1) **मनरेगा:-** उप विकास आयुक्त के द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु जिले का कुल लेबर बजट 8910.37 के विरूद्व 83.26 % राशि व्यय की गई है एवं कुल मानवदिवस सृजन 30,20,124 है, जिसमें निबंधित मजदूर परिवार 1,84,976 है। लाभुकों द्वारा मॉग के आलोक में 53,997 मजदूरों को कार्य उपलब्ध कराया गया है । श्रीमती विमला प्रधान, विधायक, सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र के द्वारा पालकोट प्रखण्ड में विभिन्न मनरेगा योजनाओं के लंबित मजदूरी भुगतान को पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। उप विकास आयुक्त के द्वारा इस संबंध में बताया गया कि मुख्य सचिव, झारखण्ड, रॉची के द्वारा इस आशय से संबंधित प्राप्त हो रहे निर्देश का अनुपालन किया जा रहा है।

2) **<u>प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना:-</u>** PMGSY के तहत निर्माणाधीन योजनाओं के संबंध में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रमीण कार्य मामले, कार्य प्रमण्डल, गुमला के द्वारा पथों की प्रगति पर विस्तृत सूचना उपलब्ध कराइ गई। उनके द्वारा बताया गया कि पथ निर्माण का कार्य 3 फेज में कराया जा रहा है। वर्तमान में 16 योजनाएँ चालू की गई है, जिसपर बरसात के बाद कार्य शुरू किया जायेगा, संभवतः मार्च 2017 तक निर्माण कार्य पूर्ण हो जायेगा। 48 सड़क निर्माण योजनाओं का विखंडन किया गया है, जिनमें 10 योजना JSRY के द्वारा कराया जा रहा है तथा संवेदक के द्वारा 11 योजनाओं पर Balance Cost में Balance work कराया जा रहा है। वर्तमान में शेष 11 योजना का DPR तैयार किया जा रहा है। 8 नई योजनाओं पर NIT के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है तथा 48 योजनाओं पर निर्माण कार्य BIT के द्वारा प्रकियाधीन है। पुनः बताया गया कि चयनित Consultant द्वारा सड़क निर्माण हेतु 301 चिन्हित गॉवों का सर्वे करा लिया गया है तथा 197 सड़कों का सर्वे चल रहा है। 104 योजनाओं के लिए अलग से Consultant द्वारा सर्वे के बाद DPR की कार्रवाई की जायेगी। <u>अंतिम रूप से चयनित 8 नई योजना की सूची सभी सदस्यों को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।</u> NPCC के द्वारा बताया गया कि विभाग के द्वारा कार्यान्वित 133 सड़क निर्माण योजनाओं में 29 योजनाएँ पूर्ण है एवं 19 योजना पर FIR किया गया है, 10 सड़कों पर Retendering होना है तथा शेष सड़क निर्माण योजना मार्च 2017 तक पूर्ण हो जायेंगी। <u>29 पूर्ण योजना की सूची विस्तृत विवरणी सहित सभी सदस्यों उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।</u> <u>समीक्षा के दौरान NPCC कार्यालय में पदाधिकारियो के अनुपस्थित रहने की शिकायत का मामला</u> सामने आया। उक्त हेतु प्रखण्डों में अवस्थित विभागीय कार्यालय में पदाधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु निदेशित किया गया। <u>प्रखण्डवार बैठक कर सभी पूर्ण योजनाओं का विभाग को हस्तांतरित कराने का निदेश दिया गया।</u> <u>आगामी बैठक में योजना की सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। सड़क योजना की गुणवत्ता की जॉच हेतु टीम का गठन करने व जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध करने का निदेश दिया गया। टीम में सदस्यों/जनप्रतिनिधियों को रखने का निदेश दिया गया। श्रीमती विमला प्रधान, माननीय विधायक, सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र के द्वारा डहुडॉड से टेंगरिया पथ जो 2009 की स्वीकृत योजना है, के निर्माण में प्रगति लाने का निदेश दिया गया।</u>

(अनुपालनः– कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रमीण कार्य मामले, कार्य प्रमण्डल, गुमला/एन.पी.सी.सी. गुमला)

3) **<u>राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यकम</u>** :- प्रभारी सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, गुमला के द्वारा बताया गया कि जिला को सभी सामाजिक सहायता कार्यकम (पेंशन योजनाओं) के लक्ष्य प्राप्त है एवं जिला में निम्न योजनाएँ संचालित है। यथा :–

1. राष्ट्रीय इंदिरा गॉधी वृद्धावस्था पेंशन योजना (60–79 वर्ष),
2. राष्ट्रीय इंदिरा गॉधी वृद्धावस्था पेंशन योजना (80 से ज्यादा वर्ष),
3. राष्ट्रीय इंदिरा गॉधी विधवा पेंशन योजना,
4. राष्ट्रीय इंदिरा गॉधी विकलांग पेंशन योजना,
5. राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना,
6. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना,
7. आदिम जनजाति पेंशन योजना,
8. राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना।

वर्तमान में आदिम जनजाति पेंशन येाजना, इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय विकलांग पेशंन योजना एवं उपयेाजना के अनुसूचित जाति के आवदेन अंचल स्तर से अप्राप्त होने की सूचना दी गई। पुनः बताया गया कि विधवा सम्मान पेंशन योजना के 3147 लाभुक को पेंशन से लाभान्वित किया गया है। प्रत्येक विधवा को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से लाभान्वित किया जाना है।

4) **<u>प्रधानमंत्री आवास योजना (सभी के लिए आवास)</u>** :- माननीय स0वि0स0, सिमडेगा, श्रीमती विमला प्रधान, सिसई एवं प्रतिनिधि सिसई एवं गुमला विधान सभा क्षेत्र के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत लाभुकों के चयन में अनियमितता होने की जानकारी दी गई। उक्त हेतु टीम का गठन कर जॉच कराने व दोषियों पर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, गुमला।)

5) **<u>प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण):-</u>** सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 के ऑकडों के आधार पर ग्रामसभा के माध्यम से लाभुक के चयन की प्राथमिकता सूची तैयार करते हुए आवाससॉफ्ट में एम0आई0एस0 प्रविष्टी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा लक्ष्य प्राप्त होने पर प्रखण्डवार प्राथमिकता सूची से लाभुकों का चयन करते हुए आवास निर्माण का कार्य कराया जायेगा। श्रीमती विमला प्रधान, माननीय स0वि0स0, सिमडेगा के द्वारा कहा गया कि पालकोट, बघिमा व टुकूटोली से एक भी लाभुकों को चयनित नहीं किया गया है। इस संबंध में उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि प्राथमिकता सूची पर आपत्ति की मॉग की गई है। इस संबंध में कुछ आवेदन प्राप्त हुए है, जिस पर नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है। पुनः सभी प्रमुख, पंचायत समिति से यह भी अनुरोध किया गया कि वैसे लाभुक जो योग्य है लेकिन उनका नाम SECC DATA में नहीं है, इस आशय का आवेदन जिला को उपलब्ध करावें ताकि नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकें।

6) **<u>स्वच्छ भारत मिशन</u>** :- कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गुमला के द्वारा बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष शौचालय निर्माण हेतु 13270 लक्ष्य के विरूद्ध 3700 शौचालय पूर्ण कर लिया गया है। गरीब जनता द्वारा राशि अनुपलब्धता के कारण शौचालय निर्माण कराने की अरूचि/असमर्थ होने की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए श्री सविन्द्र सिंह के द्वारा जनहित में शौचालय निर्माण के लिए अग्रिम राशि दिलाने का अनुरोध किया गया। <u>उक्त हेतु सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया।</u>

(अनुपालनः–कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वस्छता प्रमण्डल, गुमला ।)

7) **<u>राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यकम :-</u>** कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गुमला के द्वारा बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष 2015–16 के तहत भरनो प्रखण्ड में खरका, ग्रमीण पाईपलाईन जलापूर्ति पुनर्गठन के तहत 2 योजना चालू है, यह 2-3 माह में पूर्ण हो जायेगा। सिसई जलमीनार जलापूर्ति येाजना का कार्य शुरू हो गया है एवं टॉवर लगाया जा रहा है। पालकोट प्रखण्ड में अवस्थित जलमीनार को Phase-II से हटा दिया गया है इसका DPR तैयार हो गया है व Tender डाला गया है, इस योजना पर 02 दिनों में कार्यशुरू हो जायेगा। पुनः कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गुमला के द्वारा जानकारी दी गई कि जिला योजना अनाबद्ध निधि अंतर्गत कस्तुरबा गॉधी बालिका आवासीय विद्यालय रायडीह, विशुनपुर, पालकोट, कामडारा, घाघरा में सोलर चालित लघुपाईप जलापूर्ति योजना पूर्ण हो गई है। विधायक योजना मद (जलसमृद्धि) अंतर्गत अनुशंसित योजना (जमा कार्य के तहत) कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय कामडारा, भरनो, सिसई व बसिया तथा आश्रम बालका उच्च विद्यालय, सिसई में डीपबोरिंग का

कार्य पूर्ण है। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2016–17 में Deep Well Hand Pump का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु राज्य को भेजने की जानकारी दी गई।

समीक्षा के दौरान रायडीह प्रमुख के द्वारा जनता को सिरीज डैम से किसी तरह का लाभ नहीं होने की शिकायत की गई। जरजट्टा पंचायत में बने चैकडैम से भी लाभुकों को लाभ नहीं पहुँच रहा है, स्थल चयन में जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण ऐसा हो रहा है। गुमला विधायक के प्रतिनिधि के द्वारा तुरबुंगा में निजी भूमि पानी में डूब जाने के कारण धान की फसल बर्बाद होने की जानकारी दी गई। कार्यपालक अभियंता, लघुसिंचाई के द्वारा गार्डवाल बनाये जाने का आश्वासन दिया गया।

(अनुपालनः–कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गुमला।)

8) **<u>प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना</u>** :- जिला वन्यप्राणी प्रमण्डल पदाधिकारी, गुमला के द्वारा बताया गया कि वर्तमान में 6 वाटरशेड की योजनाएँ <u>बसिया, कामडारा, पालकोट, रायडीह, गुमला व भरनो</u> प्रखण्डों में आरंभ की गई है। P.D. IWMP के द्वारा बताया गया कि नाबार्ड के द्वारा पिछले साल जून में नया योजना गुमला में आरंभ की गई है । पुनः बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2009–10 में स्वीकृत 1 योजना जो कामडारा व बसिया प्रखण्ड में कियान्वित है वर्ष 2016–2017 में समाप्त हो जायेगी।

<u>NLRMP:-</u> इस वित्तीय वर्ष से <u>NLRMP</u> को मनरेगा के साथ जोड़ा गया है। जिसका वित्तपोषण नाबार्ड कर रहा है एवं जूरा (गुमला) में पार्ट लिया गया है। भरनो के सूपा, पालकोट के पूर्वी बागेसरा एवं कोलेंग में कार्य आंरभ है। सिलम में बागवानी दो चरण में किया जाना है। विभाग की योजना से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–जिला वन्यप्राणी पदाधिकारी, वनप्रमण्डल, राँची/जिला उद्यान पदाधिकारी, गुमला/P.D. IWMP, गुमला ।)

9) **<u>डिजिटल भारत भुअभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम</u>** :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि अभिलेख का डिजिटलाजेशन किया जा रहा है। समस्त खतियानों का Scanning का कार्य चल रहा है।

10) **<u>दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना</u>:-** कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति विभाग, विद्युत प्रमण्डल, गुमला के द्वारा बताया गया कि Electrification का कार्य पतगच्छा कोयंजली में किया जा रहा है। विशुनपुर पंचायत में पोल गिराया गया है। झारखण्ड टेक्नो प्राईवेट लिमिटेड द्वारा विद्युतिकरण हेतु सर्वे कराया जा रहा है। इसमें एजेंसी द्वारा सर्वे, सामग्री आपूर्ति एवं तार बिछाने का कार्य किया जाता है तथा विद्युत विभाग द्वारा निगरानी की जाती है। 128 गॉव के 216 टोलो में सर्वे किया गया। 3 फेज में ट्रॉसफरमर लगाया जा रहा है। 12th Plan में बसिया के 9, चैनपुर के 7, गुमला के 134, सिसई के 24 एवं भरनो के 15 विद्युतिकरण रहित गॉव में सर्वे कराया गया है। 3 सबस्टेशन सिसई, बसिया एवं रायडीह में बनाया जाना है जिसके लिए जमीन हेतु सर्वे किया जा रहा है।

11) **<u>प्रधानमंत्री फसलबीमा योजना</u>** :- विशुनपुर विधान सभा क्षेत्र के प्रतिनिधि द्वारा योजना के सही कियान्वयन किये जाने का निदेश दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि घाघरा प्रखण्ड के 5040 रू0/–का चेक वापस भेज दिया गया। पुनः जनहित में Insurance मद में आई राशि से जनता का खाता खोलने का अनुरोध किया गया। जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि पिछले वर्ष 13000 लक्ष्य था एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए 45000 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब तक 31981 किसानों का फसल बीमा कराने एवं उक्त हेतु 18.08.2016 तक फार्म भरे जाने की निर्धारित समयावधि की जानकारी दी गई। कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि 3.77 करोड की राशि गुमला जिले के लिए स्वीकृत हुआ है तथा वर्तमान में जमीन सत्यापन का कार्य प्रकियाधीन है। राज्य से आवंटन/राशि प्राप्त होने पर किसानों के राशि का वितरण किया जायेगा।

12) **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन :-** बैठक में दिव्यांग शिविर, खराब एंबुलेंस एवं स्टॉफ रिक्ति के संबंध में समीक्षा की गई। विशुनपुर में 03 में से एक एंबुलेंस खराब एवं सिसई में सभी एंबुलेंस खराब होने की जानकारी प्रतिनिधियों द्वारा दी गई है। सिविल सर्जन द्वारा उक्त के संबंध में प्रस्ताव भेजे जाने की जानकारी दी गई एवं बताया गया कि अभी तक प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है। विशुनपुर के प्रमुख के द्वारा प्रखण्ड के 06 स्वा उपकेन्द्र के बंद होने की सूचना दी गई। विशुनपुर में महिला चिकित्सक की कमी है, नियुक्ति का अनुरोध किया गया। डुमरी में मात्र एक महिला चिकित्सक होने की जानकारी देते हुए सिसई में एक पुरूष चिकित्सक बहाल करने का अनुरोध किया गया। गुमला विधायक प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि अल्ट्रासाउण्ड मशीन है, लेकिन रेडियोलोजिस्ट नहीं है। निःश्चेतक नहीं होने के कारण एक महिला के बच्चे की मौत होने की जानकारी देते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई का निदेश दिया गया। सलकाया स्वा0केन्द्र में गंदगी की समस्या के मददेनजर सफाई कर्मी बहाल करने की सलाह दी गई। उक्त के आलोक में उपायुक्त के द्वारा विभाग को निःश्चेतक की नियुक्ति के प्रस्ताव तथा पूर्णकालिक सफाईकर्मी का प्रस्ताव विभाग को भेजने हेतु निदेशित किया गया। डुमरी में पदस्थापित नर्स को रायडीह में पदस्थापित किया गया है उसे डुमरी में ही रखने का आग्रह किया गया। समीक्षा के क्रम में घाघरा प्रमुख के द्वारा स्वा0 उपकेन्द्र नहीं खोले जाने की शिकायत की गई। बैठक में श्री नीरज कुमार सिन्हा, स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता, सदर प्रखण्ड गुमला का वार्षिक वेतन अवरूद्ध से मुक्त करते हुए बकाया एरियर भुगतान कराने का निर्णय लिया गया। अध्यक्ष महोदय के द्वारा चिकित्सकों के रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति अगले वर्ष तक हो जाने का आश्वासन दिया गया। कुगॉव, कुर्गी उप स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टर के अनुपस्थित रहने की शिकायत की गई। इसपर सिविल सर्जन को डॉक्टरों से बैठक कर उपस्थिति सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–सिविल सर्जन, गुमला ।)

13) **सर्व शिक्षा अभियान :-** जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा एक नई योजना के तहत नक्सल प्रभावित व ट्रैफिकिंग के शिकार सौ बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाने की जानकारी दी गई। जिसके लिए स्थल का चयन नहीं किया गया है, गुमला नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत जगह मिलने पर विद्यालय बनाने की योजना है। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि विशुनपुर व घाघरा में इस तरह के विद्यालय पूर्व में खोले गये है। गुमला विधायक के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि मसरिया में खुले कस्तूरबा आवासीय विद्यालय नक्सल प्रभावित व ट्रैफिकिंग के शिकार सौ बच्चों के लिए ही खोल गए है। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सभी के लिए योजना के तहत शिक्षकों की उपस्थिति एवं छात्रों की संख्या में वृद्धि की निगरानी SMC द्वारा कराये जाने तथा मुखिया व जनप्रतिनिधियों के सत्यापन पर ही शिक्षकों को उनकी उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान किये जाने संबंधी आदेश से अवगत कराया गया। इस आशय के आदेश पत्र सभी सदस्यों को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। 35:1 के अनुपात में शिक्षकों के स्थानांतरण की योजना की जानकारी दी गई।

(अनुपालन–जिला शिक्षा अधीक्षक/जिला शिक्षा पदा0, गुमला)

14) **एकीकृत बाल विकास योजना :-** समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिला में ICDS अंतर्गत कुल लाभुकों (बच्चों) की संख्या 52671 है एवं उक्त हेतु 3 करोड का आवंटन प्राप्त है। उक्त राशि में से 33,48,192 की निकासी की जा चुकी है एवं 37,829 के निकासी की प्रकिया चल रही है।

समीक्षा के दौरान ऑगनबाडी केन्द्रों के संदर्भ में अध्यक्ष जिला परिषद के द्वारा बताया गया कि कई प्रखण्डों में ऑगनबाडी केन्द्र नहीं हैं एवं 156 ऑगनबाडी भवनहीन हैं। इस पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि 55 भवनों में मनरेगा के तहत कार्य चल रहा है। वर्तमान में 101 ऑगनबाडी केन्द्र बनाया जाना है। सिसई बाजारटांड में सहायिका व सेविका के चयन का निदेश दिया गया। विशुनपुर प्रखड में 5-6 वर्ष पूर्व से बन रहे ऑगनबाडी केन्द्र के अबतक अपूर्ण रहने की जानकारी देते हुए उसे पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गुमला ।)

15) **मध्यान भोजन :-** समीक्षा के कम में जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि जिला में कुल 1825 विद्यालयों में मध्यान भोजन क्रियान्वित है। जिसके लिए माह सितम्बर तक के राशन की आपूर्ति हो गई है। सिसई प्रमुख के द्वारा बताया गया कि प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के द्वारा गैस आपूर्तिकर्त्ता महमूद आलम के साथ मिलकर 165 गैस सिलेण्डर की आपूर्ति कर लिया गया है। उक्त की जॉच का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–जिला शिक्षा अधीक्षक, गुमला/जिला शिक्षा पदाधिकारी, गुमला ।)

16) **राष्ट्रीय उच्चपथ :-** कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्चपथ, गुमला के द्वारा बताया गया कि एन0एच0 बाई पास का कार्य आरंभ है। जिसमें 13 % राशि खर्च हो चुकी है। पुनः बताया गया कि एन0एच0 बाई पास पर Depression का कार्य अधूरा है एवं Maintanance का कार्य चल रहा है। वर्तमान में कोई नया निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा कार्य की प्रगति धीमी बताई गई। इसपर कार्य0 अभि0 के द्वारा बताया गया कि कार्य Consultancy के द्वारा कराया जा रहा है । उक्त हेतु 2017 में Tender आरंभ होगा व 14-06-2018 तक योजना पूर्ण हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय के द्वारा सभी तकनीकी प्रकिया पूर्ण कराकर योजना आरंभ करने क निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–कार्यपालक अभियंता,राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, गुमला।)

दिशा द्वारा कवर किये जानेवाले योजनाओं पर समीक्षोपरांत जिला के विभिन्न विभागवार योजनाओं की समीक्षा की गई । जो निम्नवत् है :–

1) **जिला कृषि विभागः-** जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बीज कय के संदर्भ में बताया गया कि 188000 हेक्टयर में धान लगाने हेतु धान बीज कय के लक्ष्य के विरूद्ध 84 % बीज का वितरण लैम्पस के माध्यम से किया गया। दलहन फसलों में अरहर – 90 %, उरद– 75%, मक्का– 91%, तेलहन में मूँगफली – 99% भूमि पर व सरगुजा– 1500 हेक्टयर पर बोया गया । बीज का वितरण आत्मा विभाग के द्वारा Demonstration के पश्चात् BTM`s के माध्यम से किया गया है।

जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि वर्ष 2016–17 में घाघरा, विशुनपुर, रायडीह सिसई, पालकोट प्रखण्ड का चयन Single Window Center योजना हेतु किया गया है। इसके तहत कृषि, भूमि–संरक्षण, गव्यविकास, मत्स्य, पशुपालन विभागों का कार्य एक साथ किया जायेगा।

2) **जिला मत्स्य विभाग :-** जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि 132 किसानों को प्रशिक्षणोपरांत बीज वितरण कराया गया है। अबतक 2380 लाख बीज वितरण किया जा चुका है। 24

एकड़ तालाब निर्माण योजना में 2 तालाब पूर्ण है। मत्स्य अँगुलिकाओं के संचयन करने हेतु Tender हो गया है। विभाग के द्वारा 60 मछुआ आवास दिये जाने की योजना है, जिसके लिए अभी आवेदन अप्राप्त है। आवेदन प्राप्त होने पर सत्यापन के पश्चात् चिन्हित लाभुकों को लाभान्वित किया जायेगा। वेदव्यास निःशक्त योजना :– 1.20 लाख प्रा0 राशि हेतु अभी दिशा–निर्देश नहीं मिला है। मनरेगा द्वारा निर्माण कराये गये डोभा में भी मत्स्यबीज वितरण कराए जाने हेतु मार्गनिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। उक्त हेतु डोभा के लाभुकों को मत्स्य पालन हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण दी जा रही है।

3) **जिला गव्य विकास विभाग:-** जिला गव्य विकास पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि जिला में वर्तमान में 25 unit (प्रति यूनिट 2 गाय) की योजना है । भावी योजना 03 गाय के 25 unit 50 % अनुदान पर दिये जाने की योजना है। जिले में डेयरी निर्माण की संभावना के संदर्भ में पृच्छा करने पर जिला गव्य विकास पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि Dairy निर्माण का निर्णय Federation के द्वारा ही लिया जाता है।

4) **जिला समाज कल्याण विभाग**:- जिला को कुल स्वीकृत 1670 ऑगनबाडी केन्द्रों में 1669 नियमित रूप से संचालित है व नियमित पोषाहार वितरण किया जा रहा है है। माह जुलाई 2016 के पोषाहार की निकासी प्रकिया चल रही है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के 640 आवेदन स्वीकृत है 640 में से 151 लाभुकों को प्रथम किस्त की निकासी 90,600 प्रकियाधीन है। जिला में 34 सेविका एवं 65 सहायिका पर चयन प्रकिया चल रही है। स्वामी विवेकानंद निःशक्त योजना :– वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु आवंटन नहीं होने को कारण जनवरी फरवरी का भुगतान लंबित है । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्राप्त आवंटन से भुगतान की जा रही है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के मई माह तक का भुगतान लाभुक को कर दिया गया है। माह जुलाई 2016 के भुगतान की प्रकिया चल रही है। विभाग की सभी योजनाओं से अर्हता रखने वाली लाभुकों को लाभान्वित करने का निदेश दिया गया।

5) **जिला पशुपालन विभाग :-** विभाग के द्वारा पशुओं का टीकाकरण कार्य किया जा रहा है। 18,000 लाख के लागत पर 50 % Combined Vaccination हो गया है। श्री सैबू जी के द्वारा पशुधन के संरक्षण व सड़कों पर यत्र–तत्र पशुओं के जमावडा से दुर्घटना से बचाव हेतु कांजीहाउस के निर्माण का अनुरोध किया गया। जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा सिसई प्रखण्ड के मुर्गू में गौशाला बनाये जाने की जानकारी दी गई। स्थानीय लोगों द्वारा रजिस्ट्रेशन कराकर गौशाला बनाये जाने की जानकारी दी गई।

6) **अन्यान्य :-**

1) श्री कमलेश उराँव, पूर्व विधायक, गुमला के द्वारा वन विभाग, जिला प्रशासन को सड़क किनारे के सभी पुराने पेड़ों को चिन्हित कर कटाई कराने का अनुरोध किया गया।

2) भरनो प्रमुख के द्वारा पंचायत समिति की बैठक विगत 6 माह से नहीं होने की जानकारी दी गई। उक्त हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को भी बताया गया है। बताया गया कि उक्त बैठक दिनांक 17-08-2016 को निर्धारित की गई है। भरनो प्रमुख के द्वारा शौचालय मरम्मति कार्य में अनियमितता बरते जाने की जानकारी दी गई।

3) श्री सविन्द्र सिंह के द्वारा टॉवर चौक में अवस्थित अत्यंत जर्जर स्थिति में एक पुराना कच्चे मकान जिसके गिरने से एक बड़ी दुर्घटना होने की संभावना जताते हुए प्रशासन के निगरानी में हटाने की कार्रवाई का अनुरोध किया गया।

अंत में, अध्यक्ष द्वारा दिशा अंतर्गत कवर किये जाने वाली योजनाओं सहित सभी विभाग की कियान्वित योजनाओं का सफल कियान्वयन कराना सुनिश्चित करने के निदेश के साथ सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

28.9.16

(श्रवण साय)
उपायुक्त–सह–सदस्य सचिव,
जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति,
गुमला।

28/10/16

(सुदर्शन भगत)
माननीय राज्य मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण
मंत्रालय, भारत सरकार–सह–अध्यक्ष,
जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति,
गुमला।